नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 268
दि. 01.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

डिजिटल विकास की बढ़ती कीमत: नौ वर्षों में दोगुना हुआ ई-कचरा देश के सामने खड़ा हुआ पर्यावरण और संसाधनों का बड़ा संकट

नई दिल्ली। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, बैटरी चालित उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल तकनीक ने लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी चुनौती भी तेजी से बढ़ी है, जिस पर अब गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चुनौती है इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-कचरे की। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हुए बताया है कि पिछले नौ वर्षों में देश में पैदा होने वाले ई-कचरे की मात्रा दोगुने से भी अधिक हो गई है। हालांकि ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी लगभग 31 प्रतिशत ई-कचरे का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तीनों पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में देश में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख 8 हजार 445 टन ई-कचरा उत्पन्न होता था। बदलती जीवनशैली, तकनीकी उत्पादों की बढ़ती खपत, उपकरणों का कम होता उपयोगकाल और तेजी से बदलती तकनीक के कारण यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2025-26 तक देश में ई-कचरे की मात्रा बढ़कर लगभग 14 लाख 14 हजार 646 टन प्रतिवर्ष पहुंच गई है। यानी नौ वर्षों में ई-कचरे का उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यदि उपभोक्ता व्यवहार और तकनीकी उत्पादों की खपत इसी गति से बढ़ती रही तो ई-कचरे की मात्रा और अधिक बढ़ सकती है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपभोक्ता देशों में तेजी से शामिल हो रहा है। स्मार्टफोन बदलने का चक्र पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया है। नई तकनीक आने पर लोग पुराने उपकरणों को बदलना पसंद करते हैं। इसी तरह घरेलू उपकरणों, कंप्यूटरों, बैटरियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी उत्पादों का जीवनकाल समाप्त होने के बाद वे ई-कचरे में बदल

जाते हैं। यदि इनका उचित प्रबंधन नहीं किया जाए तो यही डिजिटल सुविधा भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकती है।

सीएसई की रिपोर्ट बताती है कि ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की दिशा में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2017-18 में केवल 9.8 प्रतिशत ई-कचरे का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता था। अधिकांश ई-कचरा अनौपचारिक क्षेत्र में बिना सुरक्षा मानकों के अलग किया जाता था या फिर खुले में फेंक दिया जाता था। लेकिन सरकार की नीतियों, रीसाइक्लिंग क्षमता में वृद्धि और औपचारिक ई-वेस्ट प्रबंधन तंत्र के विस्तार के कारण वर्ष 2025-26 तक वैज्ञानिक निस्तारण का आंकड़ा बढ़कर 69.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

इसके बावजूद चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्पन्न होने वाले लगभग 31 प्रतिशत ई-कचरे का अभी भी सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा है। यह हिस्सा या तो अनियंत्रित रूप से कबाड़ी तंत्र में चला जाता है, या फिर खुले में जलाया जाता है अथवा सामान्य कचरे के साथ फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अनेक जहरीले रसायन वातावरण में फैलते हैं और मिट्टी, जल तथा वायु को प्रदूषित करते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार ई-कचरे को सामान्य कचरे की तरह नहीं देखा जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, निकल, लिथियम और दुर्लभ धातुओं सहित कई बहुमूल्य संसाधन मौजूद होते हैं। यदि इनका वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण किया जाए तो इन धातुओं को दोबारा उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है और आयात पर निर्भरता भी घटती है। दूसरी ओर, यदि यही उपकरण बिना किसी प्रक्रिया के नष्ट कर दिए जाएं तो बहुमूल्य संसाधन हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं।

ई-कचरे का दूसरा और अधिक गंभीर पक्ष इसमें मौजूद विषैले तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, ब्रोमिन युक्त यौगिक तथा अन्य हानिकारक रसायन मौजूद रहते हैं। यदि इन उपकरणों को खुले में तोड़ा जाए या जलाया जाए तो ये जहरीले तत्व मिट्टी, भूजल और हवा में मिल जाते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे तंत्रिका तंत्र, श्वसन प्रणाली, गुर्दे, यकृत और बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में ई-कचरे की प्रोसेसिंग भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश के अनेक हिस्सों में बिना सुरक्षा उपकरणों के श्रमिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हाथों से तोड़ते हैं या प्लास्टिक और तारों को जलाकर धातुएं निकालते हैं। इस प्रक्रिया से जहरीला धुआं निकलता है और श्रमिक सीधे विषैले रसायनों के संपर्क में आ जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि औपचारिक रीसाइक्लिंग उद्योग को मजबूत किए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

ई-कचरे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए देश में आधुनिक रीसाइक्लिंग अवसंरचना विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में दिल्ली के होलंबी कलां क्षेत्र में देश का पहला आधुनिक ई-वेस्ट पार्क विकसित किया जा रहा है। लगभग 11 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तैयार हो रहे इस पार्क की वार्षिक क्षमता एक लाख मीट्रिक टन से अधिक ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की होगी। इस परियोजना का उद्देश्य केवल कचरे का निपटान करना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद प्रत्येक उपयोगी सामग्री को अलग कर दोबारा उत्पादन प्रक्रिया में शामिल करना भी है।

इस ई-वेस्ट पार्क में अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से विभिन्न धातुओं, प्लास्टिक, कांच और अन्य घटकों को अलग-अलग कर पुनर्चक्रण के लिए तैयार किया जाएगा। इससे एक ओर बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि देश के अन्य महानगरों में भी इसी प्रकार के आधुनिक ई-वेस्ट पार्क स्थापित किए जाएं तो ई-कचरे की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

पर्यावरण विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। ई-कचरे के सुरक्षित प्रबंधन में उपभोक्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कूड़े में फेंकने के बजाय अधिकृत संग्रह केंद्रों या अधिकृत रीसाइक्लिंग एजेंसियों को सौंपना आवश्यक है। साथ ही निर्माताओं को भी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत पुराने उत्पादों की वापसी और उनके सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाना होगा।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ई-कचरे का पहाड़ भी खड़ा हो रहा है। यदि समय रहते वैज्ञानिक प्रबंधन, आधुनिक रीसाइक्लिंग व्यवस्था, सख्त नियमन और जन-जागरूकता पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया तो यह डिजिटल उपलब्धि भविष्य में पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट का रूप ले सकती है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि ई-कचरे को केवल कचरा नहीं, बल्कि मूल्यवान संसाधन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी दोनों के रूप में देखने की आवश्यकता है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज, कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला; निष्पक्ष जांच की मांग के बीच अयोध्या में बढ़ा राजनीतिक तनाव

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में अपने साथ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इन घटनाक्रमों के बाद यह मामला केवल कानूनी जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बन गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई तीखी टिप्पणियां कीं। पार्टी की ओर से साझा किए गए एक पोस्ट में लिखा गया, "मुंह में राम, बगल में छुरी। चढ़ावा चोरों से दूरी है जरूरी।" वहीं दूसरे पोस्ट में लिखा गया, "राम नाम अपना, चढ़ावे का माल अपना।" कांग्रेस ने इन टिप्पणियों के माध्यम से आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े विषय पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं

और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कथित गड़बड़ी को दुखद और शर्मनाक बताते हुए कहा कि देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने गहरी आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर निर्माण तथा उससे जुड़े कार्यों के लिए दान दिया था। ऐसे में यदि चढ़ावे के प्रबंधन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

प्रियंका गांधी ने कहा कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं और विश्वास से जुड़ा विषय है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कथित गड़बड़ी कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दान एकत्र करने वालों की जिम्मेदारी केवल धन जुटाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और उचित उपयोग सुनिश्चित करना भी उनकी जवाबदेही का हिस्सा है।

इस बीच मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और एसआईटी पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आवश्यकतानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विवाद उस समय और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने दावा किया कि अयोध्या पहुंचने के बाद उन्हें पुलिस ने नजरबंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राम मंदिर में दर्शन करने से रोका गया और देर रात होटल से हटाकर एक अतिथि गृह में ले जाया गया, जहां उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। अजय राय ने कहा कि जब तक उन्हें राम मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक वह अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक कारणों से उन्हें रोकने का आरोप लगाया और कहा कि यदि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था, तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ने उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया कि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है या केवल नजरबंद किया गया है। उनके अनुसार यदि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था, तो फिर आधी रात को उन्हें होटल से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या औचित्य था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है।

दूसरी ओर, जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य एकत्र करने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा।

साइबर ठगों पर केरल सरकार का बड़ा डिजिटल प्रहार, 2 हजार अवैध लोन ऐप और 5 हजार फर्जी वेबसाइटें बंद; ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने को तैयार होगी नई रणनीति

तिरुवनंतपुरम। डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच केरल सरकार ने साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक अभियान तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए अब तक लगभग दो हजार अवैध लोन ऐप और पांच हजार से अधिक फर्जी वेबसाइटों पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार का कहना है कि बदलते डिजिटल अपराधों की चुनौती से निपटने के लिए नई तकनीकों और आधुनिक निगरानी तंत्र पर आधारित व्यापक परियोजना तैयार की जा रही है, ताकि साइबर अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

मंगलवार को विधानसभा में इस विषय पर चर्चा के दौरान केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट आधारित वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी निवेश योजनाएं, अवैध लोन ऐप और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस लगातार तकनीकी कार्रवाई कर रही है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

गृह मंत्री यह जवाब कांग्रेस विधायक अबिन वार्की द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दे रहे थे। चर्चा के दौरान अबिन वार्की ने कहा कि केरल में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्य इस प्रकार के अपराधों के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य में साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के 42 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें लोगों को लगभग 814 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

विधायक ने यह भी बताया कि कुल वित्तीय नुकसान का लगभग आधा हिस्सा ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े फर्जी मोबाइल ऐप तथा वेबसाइटों के माध्यम से लोगों से ठगा गया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी आकर्षक मुनाफे, कम समय में अधिक रिटर्न और आसान निवेश के नाम पर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। इसके अलावा अवैध डिजिटल लोन ऐप भी लोगों का निजी डेटा हासिल कर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने स्वीकार किया कि साइबर अपराध राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने कहा कि केरल के लगभग प्रत्येक जिले से एक हजार से अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यही कारण है कि पुलिस केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अपराध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए तकनीकी निगरानी और साइबर पेट्रोलिंग को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस पीड़ितों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 के तहत मुकदमे दर्ज कर रही है। इन मामलों में आरोपियों की पहचान, डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह, बैंक खातों की जांच और ऑनलाइन लेनदेन की निगरानी के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गृह मंत्री ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति के बिना संचालित 1,836 अवैध लोन ऐप को ब्लॉक किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी निवेश योजनाओं और ऑनलाइन ठगी के लिए इस्तेमाल की जा रही पांच हजार से अधिक वेबसाइटों पर भी रोक लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि इन अवैध ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को आसान ऋण, त्वरित निवेश, अधिक ब्याज और विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लालच देकर ठगा जा रहा था। कई मामलों में लोगों का व्यक्तिगत डेटा, बैंकिंग जानकारी और मोबाइल फोन का एक्सेस लेकर उनका आर्थिक शोषण भी किया गया। सरकार का उद्देश्य ऐसे प्लेटफॉर्म को शुरुआती स्तर पर ही बंद कर देना है, ताकि नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में न फंसें।

गृह मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार अब केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि साइबर सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक रणनीति भी तैयार कर रही है। इसके तहत आधुनिक तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली, साइबर इंटेलिजेंस, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर जागरूकता अभियानों को एकीकृत करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित जांच और पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि साइबर पेट्रोलिंग को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। पुलिस की विशेष टीमें सोशल मीडिया, संदिग्ध वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके।

रोजगार के नए दौर में बदल रही तस्वीर: बड़े शहरों में घटी बेरोजगारी महिला भागीदारी और उद्यमिता ने रचा विकास का नया अध्याय

नई दिल्ली। भारत के बड़े शहरों में रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी, स्टार्टअप संस्कृति के विकास और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने शहरी श्रम बाजार को नई दिशा दी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एनएसओ) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश के 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 46 प्रमुख शहरों में पिछले सात वर्षों के दौरान न केवल बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रिपोर्ट यह संकेत देती है कि भारत के शहरी रोजगार ढांचे में अब पारंपरिक नौकरी के साथ-साथ उद्यमिता, नवाचार और महिला नेतृत्व भी विकास के प्रमुख आधार बनते जा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025 तक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बड़े शहरों में रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं। सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और छोटे व्यवसायों के विस्तार ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी में आई वृद्धि इस बात का संकेत है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एलएफपीआर) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2017-18 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 19.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 27.2 प्रतिशत हो गई। सात वर्षों में 7.4 प्रतिशत अंकों की यह वृद्धि केवल सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और बदलती सामाजिक सोच का भी संकेत है। इसका अर्थ है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक महिलाएं अब रोजगार, व्यवसाय या स्वरोजगार से जुड़ रही हैं।

महिलाओं के वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (डब्ल्यूपीआर) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में जहां यह 17.9 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2025 तक बढ़कर 25.5 प्रतिशत पहुंच गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब वास्तव में कार्यरत हैं और औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति लगातार मजबूत हो रही है।

पुरुषों की स्थिति भी पहले की तुलना में बेहतर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की श्रम भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 74.2 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 75.9 प्रतिशत हो गई। वहीं पुरुषों का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 68.6 प्रतिशत से बढ़कर 72.6 प्रतिशत तक पहुंच गया। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार दोनों वर्गों को लाभ पहुंचा रहा है।

रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू बेरोजगारी दर में आई गिरावट है। महिलाओं की बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 10.4 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार कमी दर्ज की गई। वर्ष 2025 तक यह घटकर 6.1 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार पुरुषों की बेरोजगारी दर भी वर्ष 2017-18 के 7.5 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह संकेत देता है कि देश के बड़े शहरों में रोजगार सृजन की गति पहले की तुलना में मजबूत हुई है और श्रम बाजार अधिक सक्रिय हुआ है।

हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि महिलाओं के सामने रोजगार से जुड़ने में अभी भी कई सामाजिक चुनौतियां बनी हुई हैं। रोजगार से बाहर रहने के कारणों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 53.5 प्रतिशत पुरुषों ने पढ़ाई को रोजगार में शामिल न होने का प्रमुख कारण बताया, जबकि 68.7 प्रतिशत महिलाओं ने बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों को सबसे बड़ी बाधा माना। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने के बावजूद घरेलू कार्यों का असमान बोझ अभी भी उनके रोजगार पर प्रभाव डाल रहा है।

महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 46 बड़े शहरों में से 19 शहर ऐसे हैं, जहां कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा 32 शहरों में 20 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। यह दर्शाता है कि महिलाएं अब केवल नौकरी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वयं रोजगार सृजित करने और व्यवसाय स्थापित करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

महिला उद्यमिता के मामले में सूरत, वडोदरा और पुणे जैसे शहर देश के अग्रणी केंद्र बनकर उभरे हैं। इन शहरों में 40 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर औद्योगिक वातावरण, वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता, कौशल विकास कार्यक्रम और सामाजिक समर्थन ने इन शहरों में महिला उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

देश में स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार का लाभ भी महिलाओं को तेजी से मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक भारत में 2.12 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत हैं। इनमें से 1.02 लाख से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं, जिनमें कम-से-कम एक महिला निदेशक या साझेदार शामिल है। वर्ष 2017 में ऐसे स्टार्टअप की संख्या मात्र 1,945 थी, जो 2025 तक बढ़कर 23,718 हो गई। यह वृद्धि दर्शाती है कि महिलाएं अब नवाचार आधारित उद्योगों और नई अर्थव्यवस्था में भी तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं।

सरकार की विभिन्न योजनाओं ने भी महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को मजबूती प्रदान की है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के माध्यम से लगभग 2,995 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत लगभग 294 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया गया, जबकि क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से महिला उद्यमियों को बिना पर्याप्त गारंटी के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं के लिए पूंजी जुटाने की कठिनाइयों को कम करना और उन्हें व्यवसाय विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरकार ने महिलाओं को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया है। फरवरी 2026 तक देश में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही 2.1 लाख से अधिक महिला सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इससे महिला उद्यमियों को सीधे सरकारी विभागों को उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने का अवसर मिला है।

संपादकीय

मानवता के लिए एआई के करिश्माई फायदे सामने आ रहे हैं

मानवता के लिए एआई के करिश्माई फायदे सामने आ रहे हैं। यह तकनीक स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है लेकिन इससे प्राइवेसी, रोजगार, असमानता और मानवीय मूल्यों से जुड़े खतरे भी हैं। विशेषज्ञों व नीति नियंताओं का दायित्व है कि एआई के उपयोग में मानवीय गरिमा तथा प्रभावी वैश्विक नियमन को प्राथमिकता मिले। मानवता की सेवा में विज्ञान और नवाचार की असीम संभावनाओं का उपयोग करते हुए, मानव इतिहास के सबसे अहम दौर में, एआई क्रांति एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में दिखाई देती है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व चुनौतियों से निबटने में सशक्त बनाने वाली इसकी क्षमता उपलब्धियों पर गर्व करने को जायज ठहराती है, वह उपलब्धि जिससे देवता तक इर्ष्या करें, जो मानवता की संयुक्त आविष्कारक क्षमता का सम्मान है। दोहराव वाले ऊबाऊ कार्यों का स्वचालन कर फुर्सत के लिए समय उपलब्ध कराना, जरूरी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, चिकित्सा में नई खोजें, दीर्घायु बनाना और बेहतर स्वास्थ्य सेवा यकीनी बनाना, जिसमें कैंसर जांच और घातक बीमारियों का पूर्वानुमान भी शामिल है, रोगियों की रोबोटिक देखभाल, वंचित वर्गों को मदद का अधिक प्रभावी और लक्षित वितरण, सभी के लिए शिक्षा और ज्ञान तथा आपदा प्रबंधन व मौसम पूर्वानुमान सहित अनेक तरीकों से पर्यावरण सततता बनाने में व्यापक योगदान, ये सभी अधिक समावेशी विकास उद्देश्य की दिशा में एआई के कुछ सबसे अहम योगदान हैं। फिर भी, मानव समाज के भविष्य और 'बुद्धिमत्ता की नियति' से जुड़े प्रश्नों पर दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, नेताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। इनमें से कुछ उस एआई के भावी विकास व क्रियान्वयन पर विराम लगाने की अपील करते हैं, जो हमारी मानवता की अवधारणा को ही अपहृत कर सकती हो। वहीं एआई समर्थकों के दावे हैं कि इसकी मदद से वस्तुओं एवं सेवाओं की 'अद्भुत प्रचुरता' बनेगी और चेतावनी देते हैं कि नियमन से वैज्ञानिक प्रगति धीमा करने से उन अहम प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जो मानवीय संवेदनाओं और सहस्राब्दियों तक चली सांस्कृतिक विकास-यात्रा के जरिये हमारे अस्तित्व की गहराइयों में समाहित भावनाओं के आधार पर नैतिक सुरक्षा-सीमाओं की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। हम कौन हैं, और क्या हम मानवता के ऐसे नए नैरेटिव के लिए तैयार हैं जिसमें कार्यात्मक दक्षता और वादे मुताबिक भौतिक समृद्धि, मानवीय आकांक्षाओं व भावनाओं की गरिमा पर हावी हो जाए, यह एक अपरिहार्य प्रश्न है, जिसने तकनीकी चमत्कारों के आकर्षण में बहने को रोके रखा है। यह इसलिए अहम है कि एआई तकनीक मानवीय भावनाओं और अंतर्ज्ञान को समझने सहित संज्ञानात्मक कौशलों की नकल कर सकती है, व कई बार बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है। क्या हम अनंत तकनीकी उथल-पुथल और रोजगार बाज़ार में दीर्घकालिक अस्थिरता से पैदा 'तनाव की वैश्विक महामारी' के लिए तैयार हैं, साथ ही 'बेकार' हुए करोड़ों लोगों की अनुमानित भीड़ के लिए, जिसे तकनीकी परिवर्तन के प्रभावों से तालमेल बैठाने में असहनीय तनाव झेलना पड़ेगा? क्या हमारे पास ऐसे सामाजिक-आर्थिक मॉडल हैं जो व्यक्ति का आत्मसम्मान बचा पाएं और सबके लिए अपनत्व व भावनात्मक कल्याण से पूर्ण जीवन यकीनी बनाएं? ये दार्शनिक प्रश्न इंसानी नजरिये से पैदा होते हैं, जिसकी नींव मानवीय मूल्यों पर टिकी है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है कि 'मन के उस गुप्त क्षेत्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जहां से भावनाएं जन्मती हैं, प्रेरणा बहती है, व इच्छाएं स्पंदित होती हैं- मानवीय आत्मा का वह आत्मपरक पक्ष जो हम सब को अनिवार्यतः वह बनाता है, जो हम हैं'। डेटा गोपनीयता की कमजोरियां, दुष्प्रचार का प्रसार, चुनावी हेराफेरी, सुपर इंटेलिजेंट हथियार प्रणालियों के नियंत्रण से बाहर हो जाने की संभावना, एआई-सक्षम फ़िशिंग मुहिम तथा निगरानी एवं सेंसरशिप- ये कुछ भयावह संकेत हैं जो किसी प्रभावी वैश्विक नियामक के अभाव में सामाजिक उथल-पुथल की वजह बन सकते हैं। राष्ट्र और राज्यों की डिजिटल संप्रभुता बनाए रखना चुनौती है, क्योंकि डेटा पर नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा और देशों की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा है। इसलिए, एआई की वह दुनिया, जो मानवता का भविष्य बदलने में सक्षम है, उसे ऐसी नैतिक दृष्टि चाहिये जो तकनीकी प्रगति का तालमेल अच्छे और खुशहाल समाज की जरूरतों से बिठा सके। अति आत्मविश्वास बोध को टेरी ईगलटन ने ऐसे व्यक्त किया: 'अति आत्म-विश्वास अंततः विनाशकारी होता है, जिसने प्राचीन यूनानियों को भय के चलते आकाश की ओर देखने पर विवश कर दिया था'। स्पेनी दार्शनिक जोसे ओर्तेगा वाई गासेट याद दिलाते हैं 'हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जब मनुष्य स्वयं को बेहद सक्षम मानता है, परंतु उसे नहीं पता कि क्या सृजित करे। वह सबका स्वामी है, किंतु खुद का नहीं। पहले से अधिक साधन, ज्ञान और तकनीक होने के बावजूद, आज की दुनिया भी उसी दिशा में जा रही जिस दिशा में अब तक की सबसे बुरी दुनिया गई थी'।

भरोसे के संकट को दूर करने की जरूरत

> “अगर थोड़ा-सा विश्वास वरिष्ठ शिक्षक जनों पर करके परीक्षा प्रणाली को उनके हवाले कर दिया जाता तो शिक्षक अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हुए अपनी अंतरात्मा का हनन कभी नहीं करेंगे।

सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में ज्ञानार्जन की समस्या है, पुस्तक संस्कृति के घटते जाने की समस्या है। हमने 2024 में नीट की परीक्षा आयोजित की। नकल और अवैध तरीकों के इस्तेमाल के कारण परीक्षा की शुद्धता बुरी तरह से प्रभावित हुई और लाखों छात्रों को पुनः परीक्षा देनी पड़ी। यदि इस अनुभव से सबक लेते तो इस बार दोबारा परीक्षाएं आयोजित न करनी पड़ती। लेकिन 2026 में जब फिर नीट परीक्षा आयोजित हुई तो फिर पेपर लीक का मामला उजागर हुआ। इस घटनाक्रम ने देश की पठन-पाठन, शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन की शुचिता के बारे में बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। भारत के युवाओं का भविष्य सटीक ज्ञान के बगैर अधूरा है और चोर गलियों से सफलता के प्रतिमान स्थापित नहीं किए जा सकते।

देश में नीट की परीक्षा दूसरी बार जिस तरह आयोजित हुई, जिनकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल, टेलीग्राम एप को बंद कर देने जैसे उपाय छात्रों को त्रिस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षा केन्द्रों में भेजा गया। बायोमीट्रिक जांच हुई, फिजिकल जांच हुई, दूसरे दस्तावेज जांचे गए। सात लाख सुरक्षा कर्मी और पर्यवेक्षक तैनात रहे। हर परीक्षा कक्ष में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया।

करीब 1.38 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 95 हजार कक्षों पर नजर रखी गई और छात्र जाम में न फंसें, इसलिए प्रधानमंत्री भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुके रहे। इसके बावजूद बिहार में 9 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए । जिनमें 7 मेडिकल के छात्र थे। सबसे पहले जब पहली बार परीक्षा हुई तो 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, इस बार दोबारा परीक्षा हुई तो 20 लाख छात्र परीक्षा देने बैठे। पहला सवाल यही है कि दो लाख से अधिक छात्र दोबारा क्यों नहीं बैठे? चाहे रिपोर्ट कहती है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और कहीं गड़बड़ी की सूचना नहीं है। लेकिन गड़बड़ी तो पहले ही पैदा हो गई थी जब पहली परीक्षा के बाद दोबारा परीक्षा की घोषणा से पूरे देश में अवसादग्रस्त होकर कई युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

केन्द्र सरकार के दर्जनों मंत्रालयों के साथ राज्य सरकारों व एजेंसियों ने 37 दिनों तक एकजुट होकर काम किया। यह सही है कि परीक्षाएं पूरी तरह से सफल रहने की घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन असल में ये कितनी सफल हुई हैं इसका पता तो परिणामों की घोषणा के साथ ही चलेगा। शिक्षाविदों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अचानक इतने वर्षों के बाद परीक्षा व्यवस्था इतनी भयावह समस्या क्यों बन गई कि इसके आयोजन के लिए वायुसेना से लेकर लाखों पुलिसकर्मियों की मदद लेनी पड़ी; और इसके बावजूद बड़े पैमाने पर नकल करते हुए छात्र पकड़े जा रहे हैं। क्या इस स्थिति का मूल कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति पैदा हुआ अविश्वास है?

आज कुछ संस्थाएं परीक्षा की ठेकेदारी कर रही थीं, उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पेपर लीक किए हैं। क्यों विद्यार्थियों पर इतना अविश्वास किया गया कि उनके परीक्षा केन्द्र बदलकर उन्हें दूर-दूर तक परीक्षा देने जाना पड़ा। जैसे पहले के वर्षों में चलता रहा है क्या उसी तरह से परीक्षाएं उन्हीं केन्द्रों में नहीं करवाई जा सकती थीं, जहां से छात्र संबंध रखते थे।

अगर थोड़ा-सा विश्वास वरिष्ठ शिक्षक जनों पर करके परीक्षा प्रणाली को उनके हवाले कर दिया जाता तो शिक्षक अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हुए अपनी अंतरात्मा का हनन कभी नहीं करेंगे अभी भी 90 प्रतिशत शिक्षक ऐसे ही हैं। उन मासूम छात्रों के बारे में सोचा जाए जिन्होंने दिन-रात एक करके पूरी मेहनत से परीक्षाएं दीं लेकिन अचानक उन्हें यह संदेश दिया गया कि पिछली मेहनत व्यर्थ है, अब दोबारा परीक्षा दो। हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान यही है कि परीक्षा लेने वालों और परीक्षा देने वालों पर पूरा विश्वास किया जाए। उनके लिए सुविधाजनक केंद्र बनाए जाएं। तब असामाजिक तत्व सारा तंत्र बिगड़ने पर आमादा हो जाएं तो उन्हें चुनकर बाहर फेंकना आसान हो जाएगा।

इस समय परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। यह नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, पूरी मेहनत और शिक्षण और शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण के बिना नहीं हो सकता। अपराधी तलाश करने की जगह छात्रों की मेहनत और अध्यापकों के नैतिक कर्तव्य पर विश्वास को प्राथमिकता दी जाए तो परीक्षाओं की ईमानदारी से करवाने की इस जटिल गुत्थी को सुलझाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। आने वाला भारत डिजिटल होने जा रहा है। यहां शिक्षा के अलग-अलग आयामों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। एआई तकनीकें सामने आ रही हैं। साइबर शक्ति बढ़ रही है। इन्हें सीखने का क्रम चलता रहे और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो हर वर्ष ऐसे एक देश एक परीक्षा जैसे आयोजन निरापद ढंग से पूरे हो सकेंगे।

प्रेरणा

जहाँ सत्य ने तोड़ीं दीवारें और सादगी बनी सबसे बड़ी शक्ति : संत कबीर की अमर वाणी का युगांतकारी संदेश

भारतीय सभ्यता का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि उन संतों, मनीषियों और विचारकों का भी इतिहास है जिन्होंने अपने ज्ञान, तप और लोकमंगल की भावना से समाज को नई दिशा प्रदान की। जब-जब मानव जीवन अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, धार्मिक कट्टरता और नैतिक पतन की ओर बढ़ा, तब-तब भारत की पवित्र भूमि से ऐसे महापुरुष प्रकट हुए जिन्होंने अपने विचारों के प्रकाश से जनमानस को जागृत किया। संत कबीरदास ऐसे ही युगप्रवर्तक संत थे, जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय समाज को केवल आध्यात्मिक संदेश ही नहीं दिया, बल्कि उसे आत्मचिंतन, विवेक और मानवीय मूल्यों का दर्पण भी दिखाया। उनकी वाणी में विद्रोह था, पर वह विनाश का नहीं, बल्कि जागरण का विद्रोह था। उसमें प्रेम था, पर वह केवल भावुकता नहीं, बल्कि मानवता को जोड़ने वाला सार्वभौमिक प्रेम था। उनकी साधारण जीवनशैली और असाधारण चिंतन ने उन्हें भारतीय संस्कृति का ऐसा अमर प्रतीक बना दिया, जिसकी प्रासंगिकता समय के साथ और अधिक बढ़ती जा रही है।

कबीर पंथ के अनुसार संत कबीरदास का जन्म संवत 1455 विक्रमी अर्थात 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ था। उनके गुरु महान वैष्णव संत स्वामी रामानंद थे, जिनकी कृपा से कबीर के भीतर भक्ति और आत्मज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ। कबीर ने स्वयं अपनी वाणी में स्वीकार किया कि उनके जीवन का आध्यात्मिक मार्गदर्शन रामानंद से ही हुआ। जन्म की कथाओं और किंवदंतियों से परे यदि उनके जीवन का मूल्यांकन किया जाए, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी पहचान किसी वंश, जाति या कुल से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से बनाई। यही कारण है कि वे किसी विशेष समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के संत कहलाए।

कबीरदास का जीवन अत्यंत सादा था। वे बुनकर का कार्य करते थे और अपने श्रम से परिवार का पालन-पोषण करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से भाग जाना है। वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्चतम आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक बने। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जंगलों में भटकने या विशेष वेशभूषा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य अपने दैनिक कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और निष्काम भाव से करे, तो वही उसकी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। उनके लिए श्रम सम्मान का विषय था और आत्मनिर्भरता आध्यात्मिक अनुशासन का एक अनिवार्य अंग।

मध्यकालीन भारत में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की रूढ़ियां और कर्मकांड समाज पर हावी हो चुके थे। एक ओर जाति व्यवस्था ने मनुष्यों के बीच ऊंच-नीच की गहरी खाई बना दी थी, तो दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता ने समाज को अनेक भागों में विभाजित कर दिया था। कबीर ने इन दोनों स्थितियों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों के बाहरी आडंबरों पर प्रश्न उठाए और कहा कि यदि मन शुद्ध नहीं है तो बाहरी पूजा-पाठ या धार्मिक प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं। उनके अनुसार ईश्वर किसी विशेष स्थान में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को पहले अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। यही सच्ची उपासना है और यही वास्तविक धर्म भी।

कबीरदास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने समाज की आलोचना केवल शब्दों से नहीं की, बल्कि स्वयं अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाया जिनका वे उपदेश देते थे। वे न किसी राजा के दरबार में सम्मान पाने की इच्छा रखते थे और न ही किसी धार्मिक संस्था के सर्वोच्च पद की आकांक्षा। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनसाधारण का विश्वास था। वे साधारण लोगों के बीच बैठते, उनकी समस्याएं सुनते और अत्यंत सरल भाषा में जीवन का गूढ़तम दर्शन समझाते थे। यही कारण है कि उनकी वाणी गांवों की चौपालों से लेकर संतों की सभाओं तक समान रूप से लोकप्रिय हुई और आज भी जनमानस की स्मृति में जीवित है।

कबीर का व्यक्तित्व धार्मिक समन्वय का अनुपम उदाहरण था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय उन्हें समान श्रद्धा से देखते थे। उनके जीवन के अंतिम प्रसंग से जुड़ी कथा आज भी सांप्रदायिक सौहार्द का अद्वितीय प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके देहावसान के बाद जब हिंदू और मुस्लिम उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे, तब कफन हटाने पर वहां शरीर के स्थान पर केवल पुष्प दिखाई दिए। दोनों समुदायों ने उन पुष्पों को समान रूप से बांट लिया और अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया। यह कथा इस सत्य को रेखांकित करती है कि कबीर का जीवन किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि मानवता का था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सभी का हो जाता है।

उनकी सादगी का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग संत तुलसीदास से जुड़ा हुआ है। जब तुलसीदास उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीर की झोपड़ी कसाइयों की दुकानों के बीच स्थित है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना बड़ा संत ऐसे स्थान पर क्यों रहता है। कबीर ने अपने व्यवहार से स्पष्ट कर दिया कि बाहरी वातावरण से अधिक महत्वपूर्ण मन की निर्मलता होती है। यदि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है तो संसार का कोई भी स्थान साधना के योग्य बन सकता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता स्थान, वस्त्र या बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र और दृष्टिकोण में निवास करती है।

कबीर स्वयं को कभी विद्वान नहीं बताते थे। वे बड़े विनम्र भाव से कहते थे कि उन्होंने कागज और कलम का सहारा नहीं लिया, फिर भी उनकी वाणी में ऐसा गहन दर्शन समाहित है जो अनेक ग्रंथों के अध्ययन से भी प्राप्त नहीं होता। उन्होंने जीवन के सत्य को अनुभव के आधार पर समझा और उसी अनुभव को सरल लोकभाषा में व्यक्त किया। यही कारण है कि उनके दोहे और साखियां आज भी उतनी ही सहजता से समझी जाती हैं जितनी सदियों पहले समझी जाती थीं। उन्होंने ज्ञान को अहंकार का नहीं, बल्कि आत्मबोध का माध्यम माना। उनके अनुसार वह ज्ञान व्यर्थ है जो मनुष्य को विनम्र न बनाए और समाज के कल्याण में उपयोगी न हो।

संत कबीरदास महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति, वर्ण, ऊंच-नीच, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव का जीवन भर विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं, इसलिए किसी को ऊंचा या नीचा मानना ईश्वर की सृष्टि का अपमान है। उन्होंने उस समय के सामाजिक ढांचे को चुनौती देते हुए कहा कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके आचरण, कर्म और नैतिकता से होती है।

Gold Rate लगातार गिर रहे हैं, ऐसे में सस्ता सोना खरीदें या घर का पुराना सोना जल्द से जल्द बेच दें?

सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव ने भारतीय परिवारों के व्यवहार में बड़ा बदलाव ला दिया है। इस वर्ष की शुरुआत में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद अब सोने के दामों में गिरावट आने लगी है, जिससे लोगों के बीच यह आशंका बढ़ रही है कि सोने की कीमतें अपनी ऊंचाई पार कर चुकी हैं। इसी डर के कारण देशभर में लोग पुराने गहने और जमा सोना तेजी से बेच रहे हैं ताकि कीमतों में और गिरावट आने से पहले वे अच्छा लाभ हासिल कर सकें। इस सबके बीच वह लोग भारी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं जिनके घर में शादी हैं। वह यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि सोना खरीदें या नहीं। जहां तक लोगों द्वारा पुराना सोना बेचे जाने की बात है तो आपको बता दें कि भारत बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, अप्रैल से जून तिमाही के दौरान लगभग पचास टन पुराना सोना बेचा गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब तैंतालीस प्रतिशत अधिक है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष की शुरुआत में सोने का भाव लगभग एक लाख अस्सी हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में यह घटकर लगभग एक लाख चालीस हजार रुपये रह गया। अब उपभोक्ताओं को आशंका है कि कीमतें और गिरकर एक लाख बीस हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच सकती हैं। इसी वजह से लोग पुराने गहनों को नए गहनों से बदलने की बजाय सीधे बेचकर नकदी प्राप्त करना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। भारत बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारतीय उपभोक्ता ऊंचे दामों का फायदा उठाकर नकदी जुटा रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि कीमतों में और गिरावट की आशंका ने लोगों को सोना बेचने के लिए प्रेरित किया है। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत आर्थिक फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश के संगठित स्वर्ण पुनर्चक्रण उद्योग को भी मजबूती मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब लोग सोने को केवल आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि एक वित्तीय संपत्ति के रूप में देखने लगे हैं, जिसे अनुकूल कीमत मिलने पर नकदी में बदला जा सकता है। यही कारण है कि घरों में वर्षों से पड़ा निष्क्रिय सोना अब बाजार में वापस आने लगा है। इससे रिफाइनरी और आभूषण उद्योग को पुनर्चक्रण योग्य सोने की लगातार आपूर्ति मिल रही है। साथ ही सोने की कीमतों में गिरावट ने बाजार में यह बहस तेज कर दी है कि क्या आने वाले समय में सोना अपनी पारंपरिक चमक खो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की उपयोगिता पूरी तरह समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन इसकी दिशा अब कई वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करेगी। देखा जाये तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई कमजोरी के पीछे मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ती बांड आय और मजबूत डॉलर जैसे कारण माने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर आर्थिक स्थिरता बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने से दूरी बनाकर शेयर बाजार और अन्य परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि हाल के महीनों में सोने की मांग पर दबाव देखा गया है।

इसके बावजूद विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की अहमियत पूरी तरह कम नहीं होगी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार अपने भंडार में सोना जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुद्राओं के अवमूल्यन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की चिंता बनी हुई है। यही कारण है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद सोने को पूरी तरह कमजोर निवेश नहीं माना जा रहा। भारत जैसे देशों में भी सोने की भूमिका बदल रही है। पहले जहां सोना मुख्य रूप से गहनों और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा था, वहीं अब इसे निवेश और वित्तीय सुरक्षा के साधन के रूप में अधिक देखा जा रहा है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत में गहनों की मांग घटी है, लेकिन निवेश के रूप में सोने की खरीद बढ़ रही है। ऊंची कीमतों के कारण लोग भारी गहनों की बजाय हल्के आभूषण, सिक्के और डिजिटल माध्यमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

इस सबके बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट का लाभ उन परिवारों को उठाना चाहिए जिनके घर में जल्द ही शादी होने वाली है? इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात शादी के मौसम के दौरान गहने खरीदने वालों के लिए पूरी तरह खराब भी नहीं हैं और पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं हैं। बाजार के संकेत बताते हैं कि सोने की कीमतों में हाल के सप्ताहों में अच्छी गिरावट आई है, जिससे शादी के लिए खरीदारी करने वाले परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार जून महीने में सोना करीब पंद्रह हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक सस्ता हुआ है। कई शहरों में लगातार चार सप्ताह से कीमतों में नरमी बनी हुई है। ऐसे में शादी के लिए गहने खरीदने वाले परिवार दो हिस्सों में बंटे दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग मान रहा है कि मौजूदा गिरावट खरीदारी का अच्छा अवसर है, क्योंकि कुछ महीने पहले की तुलना में कीमतें काफी नीचे आ चुकी हैं। दूसरी तरफ कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में यह आशंका बनी हुई है कि सोना और सस्ता हो सकता है। बाजार विश्लेषकों की राय है कि यदि किसी परिवार को अगले दो से तीन महीनों में शादी के लिए गहनों की निश्चित जरूरत है, तो पूरी खरीदारी एक साथ करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदना अधिक समझदारी हो सकती है। इससे कीमतों में और गिरावट आने पर औसत लागत कम रखने में मदद मिलेगी। साथ ही भारी और पारंपरिक डिजाइन की बजाय हल्के तथा कम मेकिंग चार्ज वाले गहनों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब गहनों को केवल परंपरा नहीं बल्कि निवेश के नजरिये से भी देखने लगे हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि दीर्घकाल में सोना अभी भी सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। साथ ही वैश्विक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

अभियान

जब भगवान भी लेते हैं विश्राम : जगन्नाथ धाम की 'अनासर' परंपरा में आस्था, आयुर्वेद और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम

भारत की सनातन परंपरा केवल पूजा-पद्धतियों और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ईश्वर और भक्त के बीच ऐसे आत्मीय संबंध की स्थापना करती है, जिसमें भगवान केवल पूजे जाने वाले देव नहीं, बल्कि परिवार के सबसे प्रिय सदस्य के रूप में देखे जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय मंदिर परंपराओं में भगवान को जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोजन कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है और यहां तक कि उनके अस्वस्थ होने पर उपचार भी किया जाता है। इस जीवंत परंपरा का सबसे विलक्षण और भावनात्मक स्वरूप ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलता है, जहां प्रतिवर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों से स्नान कराने के उपरांत "ज्वर" आ जाने की मान्यता है। इसके बाद वे चौदह दिनों तक एकांतवास में रहते हैं। इस अवधि को 'अनासर' या 'अनवसरा' कहा जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस गहरी संवेदना का प्रतीक है, जिसमें भगवान को भी मनुष्यों की तरह प्रेम, सेवा, विश्राम और उपचार की आवश्यकता वाला सजीव स्वरूप माना जाता है।

स्नान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ की वार्षिक प्रमुख लीलाओं में से एक है। इस दिन मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विग्रहों को विशेष रूप से स्नान मंडप पर लाया जाता है। यहां वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और भक्तों के जयघोष के बीच 108 स्वर्ण एवं रजत कलशों में भरे पवित्र जल से उनका महाभिषेक किया जाता है। इन कलशों का जल मंदिर परिसर के पवित्र 'सुना कुआँ' सहित विभिन्न धार्मिक स्रोतों से विधिपूर्वक लाया जाता है। स्नान के दौरान चंदन, सुगंधित द्रव्य, औषधीय तत्व और पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। यह अनुष्ठान हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है, जिसमें भगवान को ब्रह्मांड के अधिपति होने के साथ-साथ भक्तों के बीच रहने वाले जीवंत देवता के रूप में देखा जाता है।

मान्यता है कि 108 कलशों से होने वाले इस भव्य स्नान के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है। आधुनिक दृष्टि से यह प्रतीकात्मक लग सकता है, लेकिन सनातन परंपरा में इसका अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक अर्थ है। यह संदेश दिया जाता है कि भगवान अपने भक्तों के सुख-दुख, स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियों से स्वयं को अलग नहीं रखते। वे मानव जीवन की प्रत्येक अनुभूति को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का बीमार होना किसी चमत्कार की कथा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच आत्मीयता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। इस परंपरा के माध्यम से यह भावना भी व्यक्त होती है कि ईश्वर अपने भक्तों के कष्टों को स्वयं पर ग्रहण करते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए हर अनुभव से गुजरते हैं।

भगवान के अस्वस्थ होने के साथ ही पुरी के श्रीमंदिर में 'अनासर' अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। इस अवधि में भगवान को सार्वजनिक दर्शन से दूर रखा जाता है और मंदिर के मुख्य कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। चौदह दिनों तक भगवान एक विशेष कक्ष में विश्राम करते हैं, जहां केवल चुनिंदा सेवायतों और पारंपरिक राजवैद्यों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। इन दिनों भगवान की सेवा अत्यंत गोपनीय और विधिपूर्वक संपन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी रोगी को पूर्ण विश्राम, औषधि और नियंत्रित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। यह व्यवस्था भारतीय चिकित्सा परंपरा और धार्मिक विश्वास के अद्भुत समन्वय का परिचायक है।

अनासर काल में भगवान को सामान्य दिनों की तरह महाप्रसाद नहीं अर्पित किया जाता। इसके स्थान पर उन्हें हल्का, सुपाच्य और औषधीय गुणों से युक्त आहार दिया जाता है। फल, पनीर, औषधीय जड़ी-बूटियों से निर्मित विशेष लड्डू, काढ़े और पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण उनके भोग में शामिल होते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय आयुर्वेद की उस प्राचीन समझ को भी दर्शाती है जिसमें रोग की अवस्था में भोजन और औषधि दोनों को समान महत्व दिया जाता है। भगवान के उपचार की यह पूरी प्रक्रिया इस बात का संदेश देती है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संयमित आहार, विश्राम और प्रकृति आधारित चिकित्सा का विशेष महत्व है। अनासर अवधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इस दौरान भगवान के विग्रहों का विशेष श्रृंगार और पुनर्सज्जा की जाती है। स्नान के कारण विग्रहों पर लगे प्राकृतिक रंगों और अलंकरणों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए पारंपरिक चित्रकार परिवार भगवान के स्वरूप का पुनः रंग-रोगन करते हैं। इस प्रक्रिया को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे पीढ़ियों से विशिष्ट सेवायत परिवार निभाते आ रहे हैं। प्राकृतिक रंगों, वनस्पति आधारित पदार्थों और पारंपरिक तकनीकों से भगवान के दिव्य स्वरूप को पुनर्जीवित किया जाता है। जब अनासर समाप्त होता है, तब भगवान नवयौवन प्राप्त स्वरूप में भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। इस दर्शन को 'नवयौवन दर्शन' कहा जाता है, जिसका लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष इंतजार करते हैं।

अनासर के दौरान पुरी के श्रीमंदिर के कपाट बंद होने से श्रद्धालुओं की भक्ति रुकती नहीं, बल्कि एक नई दिशा प्राप्त करती है। इस अवधि में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु पुरी से लगभग पच्चीस किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरि स्थित अलारनाथ मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ विश्राम करते हैं, तब वे अलारनाथ भगवान के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए अनासर काल में अलारनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं और उसी श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं, जैसे वे पुरी में करते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि सनातन संस्कृति में ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भक्त की आस्था जहां पहुंचती है, वहीं उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। हर वर्ष अनासर काल में अलारनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, चिकित्सा सुविधाएं, यातायात नियंत्रण और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस अवधि को धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, बल्कि भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत को भी वैश्विक पहचान प्राप्त होती है। अनासर परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारतीय दर्शन ईश्वर को केवल सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें भावनाओं से जुड़े जीवंत अस्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। भगवान का बीमार होना, औषधि लेना, विश्राम करना और पुनः स्वस्थ होकर भक्तों के सामने आना जीवन के उस शाश्वत सत्य की ओर संकेत करता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। स्वास्थ्य और अस्वस्थता, विश्राम और कर्म, विराम और पुनः आरंभ—ये सभी जीवन के आवश्यक आयाम हैं। भगवान स्वयं इन अवस्थाओं को स्वीकार कर मनुष्य को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।

अनासर समाप्त होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नवयौवन स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके अगले चरण में विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा का शुभारंभ होता है। रथयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समानता, समरसता और जनसंपर्क का महान उत्सव है। इस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी एक साथ रथ की रस्सी खींचते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को साकार करता है जिसमें ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं और किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।

वर्तमान समय में जब जीवन अत्यधिक व्यस्त, तनावपूर्ण और भागदौड़ से भरा हुआ है, तब अनासर की यह परंपरा हमें विश्राम, स्वास्थ्य और आत्मचिंतन का महत्व भी सिखाती है। जिस प्रकार भगवान भी प्रतीकात्मक रूप से विश्राम करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी समय-समय पर अपने शरीर और मन को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। यह परंपरा हमें बताती है कि निरंतर कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण है उचित समय पर विश्राम लेकर नई ऊर्जा के साथ जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना। पुरी की अनासर परंपरा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता, आयुर्वेद की वैज्ञानिक समझ, लोकआस्था की गहराई और भगवान के प्रति आत्मीय संबंध का अद्भुत संगम है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

वडोदरा में वीजीआरसी-मध्य गुजरात के दूसरे दिन आयोजित हुआ ‘आत्मनिर्भर भारत इन एयरोस्पेस एंड डिफेंस’ विषय पर सेमिनार

- एयरोस्पेस और डिफेंस संबंधी सेमिनार में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की विशेष उपस्थिति
- ‘एक स्टार्टअप के रूप में आप सीधे रक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं :’ केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
- रक्षा क्षेत्र में चार कंपनियों द्वारा 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू, 4 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा

गांधीनगर, 30 जून : मध्य गुजरात क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के चौथे संस्करण का आयोजन 29 व 30 जून, 2026 के दौरान वडोदरा स्थित गुजरात राज्य फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (जीएसएफसी) यूनिवर्सिटी में किया गया है। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मंगलवार को ‘आत्मनिर्भर भारत इन एयरोस्पेस एंड डिफेंस’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की विशेष उपस्थिति में गुजरात में रक्षा क्षेत्र में 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू किए गए। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सहभागियों से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा उसे आगे ले जाने के लिए विभिन्न सुझाव सुने और उनके साथ संवाद किया।

रक्षा मंत्री ने सहभागियों के साथ संवाद करते हुए कहा, “औद्योगिक क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ उपस्थित स्टार्टअप्स या उद्योगों को कोई समस्या हो, सवाल हो अथवा आपके कोई सुझाव हो, तो हमें बताएँ। आप बताएँ कि सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है ? हम यह जानना चाहते हैं।”

इस अवसर पर उपस्थित सहभागियों ने टेस्टिंग सुविधाओं को ग्लोबल स्तरीय कैसे बनाया जा सके, टेस्टिंग सुविधाओं का निर्माण, रक्षा क्षेत्र में गुजरात की भूमिका, देश में बेसिक मटेरियल्स की उपलब्धता तथा गुजरात में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण और अन्य सम्बद्ध सुझाव प्रस्तुत किए।

एक स्टार्टअप के रूप में आप सीधे रक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं : रक्षा मंत्री

रक्षा क्षेत्र में कार्यरत तथा ड्रोन निर्माण करने वाले अमृत डिफेंस के फाउंडर नील वैद्य ने रक्षा मंत्री के समक्ष विनम्रतापूर्वक एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें उनके उत्पादों व सेवाओं के लिए योग्य ‘एंड यूजर’ की पहचान करने में कठिनाई आती है। इसके बारे में उन्होंने रक्षा मंत्री से मार्गदर्शन मांगा।

प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं लगातार डिफेंस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के साथ मुलाकात करता रहता हूँ। उनकी समस्याओं, उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसकी जानकारी मुझे मिलती रहती है। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। आवश्यक निर्देश मौके पर ही दे दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न कॉन्फ्रेंसें और कार्यरत लगातार होते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कोई कॉन्फ्रेंस हो या न हो, मीटिंग भी भले ही नहीं हो, एक स्टार्टअप के रूप में आप सीधे रक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।”

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण एमएसएमईस के बिना अधूरा है : अपर उद्योग आयुक्त

सेमिनार की शुरुआत गुजरात के अपर उद्योग आयुक्त तथा इंडेक्स्ट-बी के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री के. सी. संपत (आईएएस) द्वारा की गई। उन्होंने सेमिनार में होने वाली चर्चाओं का संदर्भ दिया और गुजरात के डिफेंस इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेशों से आयात किए जाने वाले रक्षा संसाधन हमारे देश में बनाए जाएँ और इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमईस) किस तरह सहायक हो सकते हैं; इस बारे में सेमिनार में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग रक्षा क्षेत्र में बहुत सहयोग कर रहे हैं। एमएसएमईस रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक पार्ट्स बना सकेंगे और उन्हें तेजी से डिलीवर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिफेंस क्षेत्र का स्वदेशीकरण एमएसएमईस के बिना अधूरा है।

इस सेमिनार में लघु उद्योग भारती के महासचिव श्री हंसराज गजेरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-गांधीनगर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सिस्टम्स) कमोडोर श्री मनीष त्रिपाठी (सेवानिवृत्त), भारतीय वायुसेना के एयर हेडक्वार्टर में एयरोस्पेस डिजाइन निदेशालय के एयर कमोडोर श्री ज्ञानदीप सिंह, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की महानिदेशक (पीसी एंड एसआई) डॉ. चंद्रिका कौशिक ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे और प्रेजेंटेशन दिए।

लघु उद्योग भारती के महासचिव श्री हंसराज गजेरा ने ‘रोल ऑफ एमएसएमईस इन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन’ (रक्षा स्वदेशीकरण में एमएसएमईस की भूमिका) विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ की पहल का स्वागत किया और कहा कि देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने एवं आत्मनिर्भरता हासिल करने में एमएसएमईस की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में एमएसएमईस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, कारण कि उनके पास इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटक (स्पेयरपार्ट्स) सप्लाई करने की क्षमता है। गुजरात के पास इस सेगमेंट के लिए एक सुदृढ़ आधार और उसमें अपार संभावनाएँ रही हुई हैं। आईआईटी-गांधीनगर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सिस्टम्स) कमोडोर मनीष त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) ने ‘द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ वॉरफेयर’ (युद्ध के बदलते परिदृश्य) विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा, “आज के समय में युद्ध की परंपरागत व्याख्या बदल रही है। डिजिटल युग में सूचना का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सुरक्षित संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

उन्होंने जोड़ा, “भविष्य की रक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, जो केवल आज की आवश्यकताएँ ही पूरी न करे, बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए भी सक्षम बने। आईआईटी-गांधीनगर जैसे संस्थानों, सरकार और सशस्त्र बलों के बीच सहयोग आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। आज युद्ध केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा; सूचना, साइबर क्षेत्र तथा नई टेक्नोलॉजी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी का विकास समय की जरूरत है।” भारतीय वायुसेना के एयर हेडक्वार्टर में एयरोस्पेस डिजाइन महानिदेशालय के एयर कमोडोर ज्ञानदीप सिंह ने एयरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष वक्तव्य देते हुए कहा, “आज के समय में सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भौतिक सीमाओं से आगे बढ़ रही हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है और रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विदेशी निर्भरता को कम करना जरूरी है।” उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक विकास, सुदृढ़ नीति ढाँचा और कुशल मानल संसाधन में निवेश पर बल देते हुए कहा, “एयरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सहयोग, नवाचार एवं त्वरित प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों तथा सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बहुत ही आवश्यक है।”

डीआरडीओ की महानिदेशक (पीसी एंड एसआई) डॉ. चंद्रिका कौशिक ने एयरोस्पेस तथा डिफेंस क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के विकास पर बल देते हुए कहा, “डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस, आकाश जैसी विभिन्न स्वदेशी रक्षा प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रककर हाइपरसोनिक सिस्टम्स, स्पेस तथा साइबर क्षमताएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेसर आधारित सिस्टम्स और सुरक्षित संचार जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।”

उन्होंने जोड़ा, “रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। सैनिकों की सुविधाएँ एवं क्षमताएँ बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने और प्रोटोटाइप विकास के लिए एमएसएमई क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एकेडेमिया, उद्योग एवं सरकार के बीच मजबूत सहयोग रक्षा क्षेत्र में भारत को अधिक आत्मनिर्भर बना सकता है।”

‘आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक : आत्मनिर्भर एयरोस्पेस और रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण’ विषय पर पैनल चर्चा

रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रेजेंटेशन तथा संबोधन के बाद ‘आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक : आत्मनिर्भर एयरोस्पेस तथा रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण’ विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा में राष्ट्रीय रक्षाशक्ति यूनिवर्सिटी के प्रो-वाइस प्रेसीडेंट श्री कल्पेश एच. वंड्रा ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई। पैनल चर्चा में यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के निदेशक (प्रोजेक्ट्स) एयर कमोडोर डॉ. जयंता कुमार साहू (सेवानिवृत्त), श्री राम एयरोस्पेस के संस्थापक एवं सीईओ श्री संदीप सतानी, फोर्ब्स 30 यू 30 एशिया 2024 में इनसाइड एफपीवी ड्रोन्स के सीईओ श्री अर्थ चौधरी, जैवल एयरोस्पेस के संस्थापक एवं सीईओ श्री विपुल वाछाणी, हजीरा स्थित एल एंड टी प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक श्री आनंद मिस्त्री, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक श्री आशुतोष सिंह बघेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री श्रीनिवास के., इन-स्पेसई के स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के निदेशक एयर वाइस मार्शल श्री धनंजय खोट (सेवानिवृत्त), गुजरात उद्योग एवं वाणिज्य मंडल (जीसीसीआई) की डिफेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन श्री अंशुल नाणावटी और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन श्री पीयूष तंबोली सहभागी हुए।

गुजरात में रक्षा क्षेत्र में 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में चार कंपनियों ने गुजरात में रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू किए। इनमें दिनेश चंद्र डिफेंस सिस्टम्स प्रा. लि. द्वारा 800 करोड़ रुपए, श्री राम एयरोस्पेस एंड डिफेंस एलएलपी द्वारा 150 करोड़ रुपए, श्री खोडियार हेवी इंजीनियरिंग प्रा. लि. द्वारा 100 करोड़ रुपए और एसआरके इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलपी द्वारा 1500 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। यह कुल निवेश 2550 करोड़ रुपए का है; जो गुजरात में खेडा, राजकोट, वडोदरा तथा अहमदाबाद में किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में होने वाले इस निवेश द्वारा 4 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। ये कंपनियाँ डिफेंस सिस्टम्स, डिफेंस संसाधन, एयरोस्पेस टूलिंग व इंजन तथा यूएवी सिस्टम्स और ऐप्लिकेशन हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र के विभिन्न स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। राज्य के उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए सेमिनार का समापन किया।

कक्षा में शिक्षक का थप्पड़ बना जिंदगी भर का दर्द, 10वीं के छात्र का फटा कान का पर्दा; अहमदाबाद की घटना ने खड़े किए स्कूलों में सुरक्षा और अनुशासन पर गंभीर सवाल

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद से शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते को झकझोर देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। निकोल क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में कथित तौर पर एक शिक्षक ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 10वीं कक्षा के छात्र को इतना जोरदार थप्पड़ मार दिया कि उसके कान का पर्दा फट गया। चोट इतनी गंभीर थी कि छात्र के कान से खून निकलने लगा और उसे सुनने में दिक्कत होने लगी। चिकित्सकीय जांच में कान के पर्दे के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना विद्यालय में शारीरिक शिक्षा (पीटी) की कक्षा के दौरान हुई। गुजराती माध्यम में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का छात्र अपने कुछ साथियों के साथ मैदान में बैठा हुआ था। उसी समय आसपास 10वीं और 12वीं कक्षा के कुछ अन्य विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजी विषय के शिक्षक लक्ष्मण वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के छात्र को खड़ा किया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि छात्र का उस शिक्षक के साथ पहले किसी प्रकार का विवाद या अनुशासनहीनता का कोई मामला भी नहीं था।

थप्पड़ लगते ही छात्र को तेज दर्द महसूस हुआ और उसके बाएं कान से खून बहने लगा। घटना के बाद विद्यालय परिसर में मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। परिजनों को सूचना मिलने पर छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कान, नाक और गला (ईएनटी) विशेषज्ञ को दिखाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि थप्पड़ का प्रभाव इतना गंभीर था कि छात्र के बाएं कान का पर्दा फट गया है। चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार की चोट सुनने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है और समय पर उचित उपचार नहीं मिलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है।

चिकित्सकीय रिपोर्ट मिलने के बाद छात्र के परिजनों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया। छात्र के पिता ने अहमदाबाद के कृष्णनगर पुलिस थाने में आरोपी शिक्षक लक्ष्मण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बिना किसी गलती के उनके बेटे के साथ शारीरिक हिंसा की गई, जिसके कारण उसे गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया। सोमवार सुबह विद्यालय के ट्रस्टी, आरोपी शिक्षक और छात्र के अभिभावकों के बीच बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षक ने कथित रूप से अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि छात्र के पिता ने केवल मौखिक स्वीकारोक्ति को पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने विद्यालय प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग की कि यदि भविष्य में उनके बेटे को इस चोट के कारण सुनने में स्थायी समस्या, कान से जुड़ी अन्य चिकित्सकीय जटिलता या बहरापन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके इलाज का पूरा चिकित्सकीय और आर्थिक दायित्व विद्यालय और संबंधित शिक्षक उठाएंगे।

परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने छात्र की स्थिति को गंभीर बताया है और आवश्यकता पड़ने पर उसके कान का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। इस कारण परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उनका कहना है कि विद्यालय बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का स्थान होता है, जहां विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। यदि शिक्षक ही हिंसक व्यवहार करेंगे तो इससे बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह घटना एक बार फिर विद्यालयों में अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ले आई है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सीखने की प्रक्रिया पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में संवाद, परामर्श और सकारात्मक अनुशासन पर जोर दिया जाता है, जबकि शारीरिक दंड को पूरी तरह अस्वीकार्य माना गया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि जांच में यह साबित होता है कि छात्र को शिक्षक के थप्पड़ से गंभीर शारीरिक चोट पहुंची है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अब चिकित्सकीय रिपोर्ट, विद्यालय प्रशासन के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

इस घटना ने अभिभावकों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। वे चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

फिलहाल छात्र चिकित्सकीय निगरानी में है और उसके उपचार की प्रक्रिया जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि विद्यालय प्रशासन भी आंतरिक स्तर पर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है। अब सभी की नजर जांच के निष्कर्ष और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है।

सूरत नगर निगम की 12 समितियों को मिला नया नेतृत्व, विकास कार्यों में तेजी लाने की तैयारी; महिलाओं और युवाओं को भी मिली अहम जिम्मेदारियां

सूरत। सूरत नगर निगम (एसएमसी) के प्रशासनिक ढांचे को नई गति देने और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की 12 वैधानिक एवं विशेष समितियों के नए चेयरमैन और उपाध्यक्षों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। लंबे समय से इन नियुक्तियों को लेकर चल रही चर्चाओं और राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी नेतृत्व ने अनुभव, संगठनात्मक सक्रियता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए नई टीम का गठन किया है। अब इन समितियों के माध्यम से शहर की आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, परिवहन, आवास, कानून, सार्वजनिक निर्माण और सामाजिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पार्टी नेतृत्व की सहमति से घोषित नई सूची के अनुसार स्वास्थ्य समिति की जिम्मेदारी अशोक रांदेरिया को सौंपी गई है, जबकि विक्रम देसाई को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति नगर निगम के अस्पतालों, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी एवं सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शहर की बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इस समिति की जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण समिति की कमान राजेंद्र पटेल को सौंपी गई है तथा शीतल प्रतीक पटेल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति शहर की सड़कें, पुल, सार्वजनिक भवन, आधारभूत ढांचा परियोजनाएं तथा अन्य निर्माण कार्यों की योजना, स्वीकृति और निगरानी का दायित्व संभालेगी। नगर निगम की विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में इस समिति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जल समिति के चेयरमैन के रूप में रश्मिबेन साबू की नियुक्ति की गई है, जबकि महेश कुमार मकवाना उपाध्यक्ष होंगे। यह समिति शहर में पेयजल आपूर्ति, जल वितरण प्रणाली, नई पाइपलाइन परियोजनाओं, जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी विषयों की जिम्मेदारी संभालेगी। तेजी से विस्तार कर रहे सूरत में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना इस समिति की प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा।

सीवरेज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गटर (सीवरेज) समिति की कमान रवींद्र विट्ठलभाई खेरनार को सौंपी गई है तथा रजनीत देसाई को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मानसून के दौरान जलभराव, सीवरेज लाइन की क्षमता बढ़ाने, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं पर यह समिति विशेष ध्यान देगी। शहरी विकास के साथ मजबूत सीवरेज व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

टाउन प्लानिंग समिति की अध्यक्षता महेंद्र देसाई करेंगे, जबकि अशोक मांगीलाल शाह उपाध्यक्ष होंगे। शहर के विस्तार, नई टाउन प्लानिंग योजनाओं, भूमि विकास, सड़क नेटवर्क और भविष्य की शहरी विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूरत के तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार को व्यवस्थित दिशा देने के लिए इस समिति के निर्णय विशेष महत्व रखते हैं।

नगर निगम के कानूनी मामलों की जिम्मेदारी कानून समिति को सौंपी गई है, जिसकी चेयरमैन मोहिनीबेन राठौड़ होंगी तथा काव्याबेन पटेल उपाध्यक्ष का दायित्व निभाएंगी। यह समिति न्यायालयों में लंबित मामलों, कानूनी सलाह, अनुबंधों और विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों के विधिक परीक्षण की निगरानी करेगी।

सोशल वेलफेयर एवं आनंद-प्रमोद सांस्कृतिक समिति का नेतृत्व राजेश राणा करेंगे, जबकि ईश्वरभाई नरोला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यह समिति सामाजिक कल्याण योजनाओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, मनोरंजन सुविधाओं तथा नागरिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।

हॉस्पिटल रिलीफ एवं हेल्थ प्रमोशन समिति की कमान अलकाबेन पाटिल को दी गई है और हेमाक्षीबेन चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति अस्पतालों में रोगी सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी।

हाउसिंग एवं पार्क्स समिति के चेयरमैन सुरेशभाई धमेलिया होंगे, जबकि विधिबेन चानाभाई राठौड़ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। यह समिति आवास योजनाओं, सार्वजनिक उद्यानों, हरित क्षेत्र के विकास और नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के विस्तार का कार्य करेगी।

स्लम इम्प्रूवमेंट समिति की जिम्मेदारी दिग्विजयसिंह बराड़ को सौंपी गई है तथा वंदनाबेन घोघरी उपाध्यक्ष होंगी। झुग्गी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, स्वच्छता, आवास सुधार और जीवन स्तर बेहतर बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लाइट एवं फायर समिति की चेयरमैन सोनूबेन आंबलिया बनाई गई हैं, जबकि सुधाबेन राजेश पांडे उपाध्यक्ष होंगी। यह समिति शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, अग्निशमन सेवाओं, आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े विषयों की निगरानी करेगी।

सार्वजनिक परिवहन समिति की कमान मनीषभाई चिमनभाई पटेल को सौंपी गई है तथा रीनासिंह अजीतसिंह राजपूत उपाध्यक्ष होंगी। यह समिति नगर परिवहन सेवाओं, बस संचालन, यातायात सुविधाओं तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी।

घोषित सूची की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। 12 समितियों में कई प्रमुख पद महिलाओं को दिए गए हैं, जिसे संगठन महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देने और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। साथ ही नए और अनुभवी नेतृत्व के संतुलन के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नगर निगम की समितियां शहर के दैनिक प्रशासन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की रीढ़ होती हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से सड़क, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, शहरी नियोजन और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में नई नियुक्तियों से विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद की जा रही है।

नगर निगम के अनुसार, 7 जुलाई को संबंधित समितियों की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में नव-नियुक्त चेयरमैन और उपाध्यक्षों की औपचारिक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद सभी पदाधिकारी अपना कार्यभार संभालेंगे और अपनी-अपनी समितियों के माध्यम से शहर के विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नगर निगम प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व दोनों को उम्मीद है कि नई टीम के गठन से सूरत में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और नागरिक सुविधाओं के संचालन को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकेगा।

यात्रियों की सुविधा हेतु अहमदाबाद मण्डल की 03 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ तथा यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने निम्नलिखित ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 20485/20486 साबरमती–जैसलमर–साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस में 02 एसी 3-टियर एवं 01 स्लीपर कोच साबरमती से 03 जुलाई, 2026 से 02 अगस्त, 2026 तक तथा जैसलमर से 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

ट्रेन संख्या 20492/20491 साबरमती–जैसलमेर–साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 02 एसी 3-टियर एवं 01 स्लीपर कोच साबरमती से 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा जैसलमेर से 02 जुलाई, 2026 से 01 अगस्त, 2026 तक अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

ट्रेन संख्या 20987/20988 उदयपुर सिटी–असारवा–उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 01 सेकेंड सीटिंग कोच असारवा से 02 जुलाई, 2026 से 01 अगस्त, 2026 तक तथा उदयपुर सिटी से 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

सुस्त मानसून से खेती पर संकट के बादल, खरीफ बुवाई में 23 फीसदी गिरावट; धान, दाल और तिलहन की कम बोआई से बढ़ी महंगाई की आशंका

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी प्रगति ने देश की कृषि व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं होने का सीधा असर खरीफ फसलों की बुवाई पर दिखाई देने लगा है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 25 जून तक खरीफ फसलों की कुल बुवाई पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून सामान्य गति नहीं पकड़ता, तो इसका प्रभाव केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महंगाई पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। विशेष रूप से धान, दालों और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के रकबे में आई उल्लेखनीय कमी ने सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और बाजार विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 25 जून तक देश में खरीफ फसलों की बुवाई केवल 182.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 236.46 लाख हेक्टेयर था। यानी एक वर्ष में लगभग 53 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो सकी। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि देश के अनेक हिस्सों में किसान अभी भी पर्याप्त वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और खेतों में बुवाई शुरू नहीं कर पाए हैं।

सबसे अधिक चिंता धान की खेती को लेकर जताई जा रही है, क्योंकि यह देश की खाद्य सुरक्षा का आधार माना जाता है। इस वर्ष धान की बुवाई में लगभग 25.17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 25 जून तक धान का रकबा घटकर केवल 25.75 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कहीं अधिक क्षेत्र में रोपाई हो चुकी थी। धान की खेती मुख्य रूप से समय पर मानसून पर निर्भर करती है और वर्षा में देरी का सीधा प्रभाव इसकी रोपाई पर पड़ता है। यदि आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं होती, तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

तिलहन फसलों की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक दिखाई दे रही है। आंकड़ों के अनुसार, तिलहन की बुवाई में 53.33 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह कमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश पहले से ही खाद्य तेलों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यदि घरेलू उत्पादन प्रभावित होता है, तो आयात पर निर्भरता और बढ़ सकती है, जिसका असर खाद्य तेलों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।

दालों की खेती भी इस बार मानसून की सुस्ती से अछूती नहीं रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, दालों का रकबा भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम हो गया है। दालें भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके उत्पादन में कमी आने पर बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी रहती है। पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि दालों की उपलब्धता में कमी होने पर सरकार को आयात बढ़ाने और बाजार हस्तक्षेप जैसे कदम उठाने पड़ते हैं।

मौसम विभाग के आंकड़े भी कृषि क्षेत्र की चिंताओं को और गहरा कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 24 जून तक देश में सामान्य से 42 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। मानसून की यह कमी केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है। सबसे अधिक प्रभावित मध्य भारत रहा है, जहां सामान्य से लगभग 59 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यह क्षेत्र सोयाबीन, कपास, दालों और अन्य खरीफ फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां बारिश की कमी का सीधा असर बुवाई और आगे चलकर उत्पादन पर पड़ सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष अल-नीनो की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल-नीनो परिस्थितियां दक्षिण-पश्चिम मानसून की तीव्रता और वितरण को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आने वाले महीनों में अल-नीनो और मजबूत होता है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि मानसून अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, फिर भी विशेषज्ञ लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सर्वसमावेशी विकास का लक्ष्य वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से चरितार्थ हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ वडोदरा में चौथी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का शानदार समापन

▸▸ 3 लाख 34 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ 3759 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

▸▸ 1 लाख 97 हजार से अधिक संभावित रोजगार के अवसर होंगे पैदा

▸▸ केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में गुजरात की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

▸▸ भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

▸▸ आज भारत आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक स्तर पर हुंकार भर रहा है

▸▸ आज भारत इंटरनेशनल फोरम में कुछ बोलता है, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है

▸▸ गुजरातियों के पास चुनौतियों को अवसर में बदलने का गजब का साहस और जज्बा है

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए अनुकूल नीतियां और वातावरण बनाया है

▸▸ वाइब्रेंट समिट और वीजीआरसी जैसे आयोजन राज्य में उद्योगों और उद्योगकारों के विकास के लिए एक टेक ऑफ प्लेटफॉर्म हैं

▸▸ मौजूदा जियो-पॉलिटिकल हालात में प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योगों की पूरी तरह से रक्षा की है

▸▸ अपना व्यवसाय-उद्योग शुरू करने की लगन रखने वाले कुशल युवाओं को इनोवेशन और स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ने का अवसर मिला है

वडोदरा : केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में मंगलवार को वडोदरा में आयोजित मध्य गुजरात क्षेत्र की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का शानदार समापन हुआ। 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' की थीम के साथ गुजरात की एक विशिष्ट पहल के रूप में वीजीआरसी के चार संस्करण गुजरात में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने चौथी वीजीआरसी की सफलता की गर्व से घोषणा करते हुए कहा कि वडोदरा में मध्य गुजरात की इस वीजीआरसी में कुल मिलाकर 3 लाख 34 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 3759 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में राज्य में 1 लाख 97 हजार संभावित रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में मुख्य भाषण देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 2014 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 46 हजार करोड़ रुपए था, जो पिछले दशक में बढ़कर 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा, भारत ने 39 हजार करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। गुजरात की धरती ने देश को महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी विभूतियां दी हैं। इसी धरती ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले भारत की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम में कुछ बोलता है, तो सारी

दुनिया कान खोलकर सुनती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया में भारत के परचम को लहराया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि गुजरात की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोगों की मानसिकता है। चुनौतियों को अवसर में बदलने का एक गजब का जज्बा और साहस है। 2003 में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात समिट की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी, जो अब दो दशकों बाद विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक आंदोलन बन गई है।

श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक विकास को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था और सुरक्षा गहराई से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी महान राष्ट्र आर्थिक ताकत, तकनीकी शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की तीन मजबूत नींवों पर खड़ा होता है। जो इन क्षेत्रों में आगे होगा, वही लीड लेगा और वहीं इनोवेशन होगा।

श्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान जियो पॉलिटिकल हालात में भारत की आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में डिफेंस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। पहले हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। हम इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस, पॉलिसी और पारदर्शिता लाकर उनमें विश्वास पैदा किया है।

डिफेंस सेक्टर में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गुजरात की रोबस्ट इंडस्ट्री, स्पिरिट और कौशल देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में बड़ा योगदान दे सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात डिफेंस क्षेत्र में हब बन सकता है।

वडोदरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने गर्व से कहा कि आज वडोदरा भारत की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का केंद्र बन गया है। टाटा-एयरबस सी-295 प्रोजेक्ट एक अभूतपूर्व मील का पत्थर है और हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने साणंद और धोलेरा के सेमीकंडक्टर हब को टेक्नोलॉजी का आधारस्तंभ बताया। रक्षा मंत्री के अनुसार गुजरात का केमिकल और पेट्रोकेमिकल का मजबूत आधार भी डिफेंस सेक्टर के उत्पादन में योगदान दे सकता है। इसके अलावा, गुजरात के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पोर्ट, मैरीटाइम और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्र भी डिफेंस प्रोडक्शन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में गुजरात को देश का लीडर बताते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्रीन एनर्जी भी डिफेंस सेक्टर के लिए नया रास्ता खोल सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी पॉलिसी हमेशा पारदर्शी रही है और हर क्षेत्र की इंडस्ट्री को पर्याप्त सहयोग दिया जाता है।

श्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक स्तर पर हुंकार भर रहा है। भारत की यह विकास यात्रा असाधारण है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि उसका निर्माण करना है, जिसमें भारत के अलग-अलग उत्पाद ग्लोबल मार्केट में हों। भारत की आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलगाव नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर सभी के साथ भागीदारी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वसमावेशी विकास का जो लक्ष्य रखा है, उसे गुजरात ने इस वीजीआरसी के माध्यम से साकार किया है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का विजन, क्षेत्रीय ताकत, परंपरा और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता इस वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के मूल में है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए अनुकूल नीतियां और वातावरण तैयार किया है। एक समय 'फ्रेजाइल फाइव' यानी पांच नाजुक में से एक मानी जाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि मौजूदा जियो-पॉलिटिकल हालात में भी प्रधानमंत्री ने उद्योगों के हितों की पूरी रक्षा की है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया को श्री मोदी साहब के नेतृत्व पर भरोसा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का भी देश के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ने से फॉरेन रेमिटेंस (विदेश से अपने परिवार या प्रियजन को पैसा भेजना) में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि 2025 के एक ही वर्ष में 13 लाख करोड़ रुपए के रेमिटेंस देश में आया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना व्यवसाय शुरू करने की लगन वाले कुशल युवाओं और छोटे-बड़े उद्योगकारों को इनोवेशन और स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि वाइब्रेंट समिट और वीजीआरसी जैसे आयोजन उद्योगों और उद्योगकारों के विकास के लिए एक टेक ऑफ प्लेटफॉर्म बन गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बतौर मुख्यमंत्री 2003 में शुरू की गई वाइब्रेंट समिट की अपार सफलता के चलते गुजरात ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा राज्य के क्षेत्रीय विकास के जरिए संतुलित विकास का एक नया अध्याय रचकर विकसित भारत 2047 के लिए सभी के सहयोग से विकसित गुजरात को आगे रखना है।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह

समापन समारोह में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने गुजरात को अंतर्देशीय मत्स्यपालन के क्षेत्र में देश का 'पावरहाउस' बनाने के लिए एक सटीक रोडमैप पेश किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात के पास न केवल लंबी तटरेखा है, बल्कि अंतर्देशीय मत्स्यपालन की अपार क्षमता भी है। राज्य के अनेक जिलों के गांवों में मौजूद तालाबों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके ब्लू इकोनॉमी को गति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उपलब्ध कुल खारे पानी का एक तिहाई हिस्सा अकेले गुजरात में है, जो झींगा के उत्पादन के लिए अत्यंत मजबूत आधार प्रदान करता है।

मछली निर्यात क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुल मत्स्य निर्यात में गुजरात के अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग का हिस्सा केवल 2 फीसदी है, जिसे बढ़ाने का बड़ा अवसर गुजरात के पास है। इसके लिए उन्होंने मत्स्यपालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, हैचरी सिस्टम को मजबूत बनाने और कोल्ड चेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने तथा श्रेष्ठ परिवहन सुविधा जैसे प्रेरक सुझाव दिए।

उन्होंने राज्य सरकार, हितधारकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों से एक साथ मिलकर गुजरात को अंतर्देशीय मत्स्यउद्योग का ग्लोबल हब बनाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉन्फ्रेंस 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के सपने को साकार करने में एक सार्थक मंच साबित होगी।

समापन समारोह में जाइडेक्स समूह के चेयरमैन श्री अजय रांका और रूबामिन के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक श्री अतुल डालमिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम की शुरुआत में उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा ने वीजीआरसी के आयोजन से लेकर सफलता तक के सारे पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया।

समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के हस्तकला कारीगरों और उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया।

समापन समारोह में राज्य मंत्री डॉ. मनीषा वकील, उद्योग जगत के अग्रणी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य सहित प्रतिनिधिगण और कई वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

जीएसएफसीयू के अध्यक्ष श्री पी.के. तनेजा ने आभार व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने पल्स पोलियो अभियान में रचा कीर्तिमान,पहले ही दिन 3,569 बच्चों का टीकाकरण कर पश्चिम रेलवे में रहा अव्वल

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभियान के प्रथम दिन ही मंडल ने 3,569 बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) की खुराक पिलाकर पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में सर्वाधिक टीकाकरण का गौरव प्राप्त किया।

28 जून, 2026 से प्रारंभ हुए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की देखरेख में किया गया। अभियान को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंडलीय रेलवे अस्पताल, 10 स्वास्थ्य इकाइयों तथा रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों सहित मंडल भर में 52 पल्स पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए, जिससे अधिकतम बच्चों तक सहज एवं त्वरित पहुंच सुनिश्चित की जा सकी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुव्यवस्थित योजना, समर्पित कार्यप्रणाली एवं चिकित्सा विभाग की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप अभियान के पहले ही दिन 3,569 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। इस उपलब्धि ने भावनगर मंडल को पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में प्रथम स्थान दिलाया।

बूथ आधारित टीकाकरण के उपरांत 29 एवं 30 जून को विशेष अनुवर्ती अभियान चलाकर चिकित्सा टीमों ने मंडल की सभी रेलवे कॉलोनियों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया। इस दौरान ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई गई, जो किसी कारणवश पहले दिन टीकाकरण से वंचित रह गए थे। इस अभियान का उद्देश्य पांच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो रोधी दवा पहुंचाना था।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि चिकित्सा विभाग की प्रभावी योजना, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों की अथक मेहनत तथा रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के सक्रिय सहयोग का परिणाम है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि भावनगर मंडल का चिकित्सा विभाग प्रत्येक बच्चे को पोलियो जैसी गंभीर एवं स्थायी विकलांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि भारत सरकार के 'पोलियो मुक्त भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान को भी रेखांकित करती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद–दरभंगा एवं गांधीधाम–भागलपुर स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार,मार्ग परिवर्तन के साथ विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा

यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन एवं आगामी त्योहारों के दौरान बढ़ती हुई यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद–दरभंगा तथा गांधीधाम–भागलपुर विशेष किराया स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए (RLDA) कार्य के कारण इन ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 09465/09466 अहमदाबाद–दरभंगा–अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद–दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) के फेरे 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा–अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक सोमवार) के फेरे 06 जुलाई, 2026 से 03 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किए गए हैं।

यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया छायापुरी, रतलाम, उज्जैन, गुना, बिना, वीरांगना

लक्ष्मीबाई झांसी, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09451/09452 गांधीधाम–भागलपुर–गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम–भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) के फेरे 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर–गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक सोमवार) के फेरे 06 जुलाई, 2026 से 03 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किए गए हैं।

यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया भचाऊ, सामाखियाली, ध्रांगध्रा, अहमदाबाद, नडियाद, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, बयाना जंक्शन, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज एवं भागलपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09465 एवं 09451 की बुकिंग 01 जुलाई, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

गांधीनगर में 127 करोड़ रुपए की लागत से होगा भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई) के नूतन भवन तथा छात्रावास का निर्माण

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में शिलान्यास किया

▸▸ आईआईटीई जैसे संस्थानों के माध्यम से भारत राष्ट्र निर्माता शिक्षक देकर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से स्थापित हुए राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई) के नए एवं अत्याधुनिक भवन का गांधीनगर में निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 127 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस नूतन भवन का मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा तथा राज्य मंत्रियों सर्वश्री त्रिकमभाई छांगा और रिवाबा जाडेजा की उपस्थिति में शिलान्यास किया।

इस प्रस्तावित नए भवन में अकादमीय भवन, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला तथा परिसंवाद सभागार और राज्य पुस्तकालय व संग्रहालय जैसी सुविधाओं के अतिरिक्त; खेलों के लिए खेल मैदान, आधुनिक सुविधाओं से युक्त 600 से अधिक छात्र-छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस आईआईटीई की स्थापना समाज को उत्तम शिक्षक उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशिष्ट विजन से की गई है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने कहा कि आज केवल भवन के निर्माण का प्रारंभ नहीं हुआ है, अपितु भारत के भविष्य के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तम शिक्षकों के निर्माण के एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। भारत केवल साधारण शिक्षक ही नहीं, वरन् 'राष्ट्र निर्माता' शिक्षक तैयार कर वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाए और विदेशों में भी श्रेष्ठ शिक्षक प्रदान करे; ऐसे भगीरथ दृष्टिकोण को यह संस्थान आज नई ऊँचाई पर ले जा रहा है।

श्री वाजा ने कहा कि विश्व स्तरीय शिक्षक तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विचार से वर्ष 2010 में इस विशिष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। संस्थान के सर्वांगीण

विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 127 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस अनुदान अंतर्गत परिसर में नए अकादमीय तथा संकाय भवनों, अत्याधुनिक वर्ग खंडों, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, परिसंवाद सभागार, स्टेट-ऑफ-द आर्ट लाइब्रेरी, संग्रहालय और खेल-कूद की उत्कृष्ट सुविधाएँ की जाएंगी। इसके अलावा; लगभग 600 से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में गुजरात देशभर में अग्रसर रहा है। यह नई शिक्षा नीति बहुविषयी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों पर विशेष बल देती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आईआईटीई को अब एक 'मल्टीडिसिप्लीनरी यूनिवर्सिटी' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न ज्ञान शाखाओं के समन्वय के साथ सर्वग्राही शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाले सात नए 'यूनिवर्सिटी स्कूल्स' का गठन किया गया है।

उन्होंने जोड़ा कि शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और शिक्षक क्लासरूम से ही राष्ट्र का निर्माण करता है। आज जिस भवन का शिलान्यास किया गया है, वह केवल सिमेंट-कंक्रीट का ढाँचा नहीं, अपितु विकसित गुजरात से विकसित भारत के उज्ज्वल भविष्य की एक सुदृढ़ आधारशिला है।

इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दार्शनिक विचार के साथ स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल अक्षर ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, अपितु शिक्षा क्षेत्र में नया चिंतन व अनुसंधान लाकर आधुनिक गुजरात और आधुनिक भारत के निर्माण में आधारभूत भूमिका भी निभाता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति के व्यापक क्रियान्वयन के बीच यह विश्वविद्यालय आगामी समय में देशभर में शिक्षा के आचार, विचार एवं व्यवहार में आमूल परिवर्तन लाकर एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वडनगर के बी. एन. हाईस्कूल में जिन आदरणीय शिक्षकों एवं गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की थी, उनका मुख्यमंत्री द्वारा भावपूर्वक अभिवादन-सम्मान किया गया।

इस अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों के करकमलों से एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) पाठ्यक्रम का डिजिटल अनावरण किया गया।

इस समारोह में गांधीनगर की महापौर श्री मीराबेन पटेल, राज्यसभा सदस्य श्री राजेश शुक्ल, आईआईटीई के प्राध्यापक, अकादमीय प्रमुख, निदेशक, प्राचार्य तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

एसआईआर के चलते मतदाता सूची से 6 करोड़ नाम हटाए गए, नागरिकों के मतदान अधिकारों और भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है और यह वर्तमान में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। रिपोर्टों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के कारण अब तक मतदाता सूची से लगभग 6 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं।

और यह एक गंभीर मामला है जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई इतने सारे लोग वोट देने के अयोग्य हैं? सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? इसके अलावा, अगर उन्हें वोट देने के अयोग्य माना जाता है, तो इससे उनके अन्य अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद ऐसी खबरें सामने आई हैं कि दोनों राज्यों की संशोधित मतदाता सूची के आंकड़ों को अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाएगा। यानी, यह आशंका है कि जिन लोगों के नाम इस नई मतदाता सूची में हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है, उन्हें इन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा।

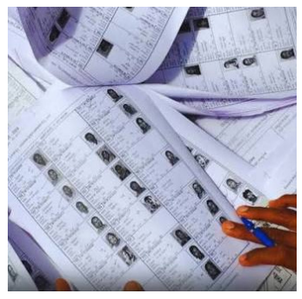

इसलिए, सूची से बाहर किए गए लोग अब अपनी नागरिकता की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से भी बाहर किए जाने का खतरा है। परिणामस्वरूप, उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि तकनीकी कारणों या समय पर दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थता के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र तभी सही मायने में फलता-फूलता है जब योग्य नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा की जाती है और चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाते हैं। तभी सच्चा लोकतंत्र देखने को मिलेगा।

आगरा में भाजपा पार्षद ने सीवर में खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाया और स्वच्छता व्यवस्था की उपेक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

आगरा में भाजपा नगर निगम कर्मचारी किशन नायक ने प्रशासन द्वारा स्वच्छता संबंधी शिकायतों की अनदेखी के विरोध में अपना जन्मदिन उफनते नाले में खड़े होकर मनाया। इस प्रतीकात्मक विरोध का उद्देश्य निवासियों द्वारा सामना की जा रही लगातार सीवेज समस्याओं को उजागर करना था। किशन नायक ने आरोप लगाया कि खुले नालों और अस्वच्छ परिस्थितियों के बारे में बार-बार शिकायत करने के बावजूद, स्वच्छता विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

अधिकारियों की निष्क्रियता ने उन्हें विरोध के अपरंपरागत तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थिति और लंबे समय से चली आ रही जन शिकायतों के प्रति स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता पर एक बहस छेड़ दी है।